राहुल गांधी 14 को करेंगे गुजरात दौरा, वलसाड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित

अहमदाबाद, 10 फरवरी (ए)। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर में 14 फरवरी को एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख अमित चावड़ा ने शनिवार को यह जानकारी दी। चावड़ा ने बताया कि राज्य में कांग्रेस कार्यकारी समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होगी। इसमें संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नव नियुक्त महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। चावड़ा ने कहा, ''राहुल जी 14 फरवरी को एक रैली में हिस्सा लेने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक राज्य में आयोजित करने के हमारे आग्रह को भी स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी कार्यसमिति की बैठक की तारीख और स्थान तय किया जाना बाकी है।

अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बोलीं- लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव

इंदौर, 10 फरवरी (ए)। लोक सभा अध्यक्ष और इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन ने आज अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों को विराम दे दिया। महाजन आज यहां अपने गृह नगर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक बहुउद्देशीय केंद्रा संकुल के भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुँची थीं। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुये स्पष्ट कहा कि वे बतौर सांसद इंदौर को बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व दे रही हैं। उन्होंने इशारों में कहा फिलहाल तो वे स्वस्थ है लिहाजा इंदौर की चाबी अपने पास ही रखेंगी। इंदौर लोकसभा सीट से आगामी चुनाव में कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके सामने चुनावी मैदान में उतारे जाने की चल रही खबरों पर महाजन ने कहा यह अच्छी बात है कि अच्छे लोग चुनाव मैदान में उतरें ...कांग्रेस का यदि कोई वरिष्ठ नेता मुझे चुनौती देता है तब मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ खबरों में श्रीमती महाजन के आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का दावा किया गया था। साथ ही इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगामी लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट से उतारे जाने की अटकलें लगायी जा रही हैं।

भाजपा के खिलाफ अपनाएं आक्रामक रुख : राहुल

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों एवं विधायक दल के नेताओं से कहा कि वे अपने राज्यों में भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएं और बेरोजगारी, कृषि संकट और केंद्र की दूसरी 'विफलताओं' से जनता को अवगत कराए। सूत्रों के मुताबिक गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक में यह बात कही। बैठक के बाद गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''आज मैंने विधायक दल के नेताओं और पीसीसी अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान हर राज्य में हमारी चुनावी तैयारियों एवं रणनीति की समीक्षा की।'' उन्होंने कहा, ''हमने आगामी चुनावों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मैं बैठक में शामिल होने की खातिर दिल्ली आने वाले नेताओं का धन्यवाद करता हूं।'' बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में शामिल नेताओं से कहा कि भाजपा के खिलाफ देश में आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां हुए भ्रष्टाचार को आक्रामकता से साथ उठाए। उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं विशेषकर बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को जनता के बीच जोर-शोर से उठाने के साथ संप्रग-1 एवं संप्रग-2 की उपलब्धियों के बारे में भी बताएं।

राफेल से भाजपा को नहीं होगा चुनाव में नुकसान : पीयूष गोयल

मुंबई, 10 फरवरी (ए)। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर विपक्ष के ''आधारहीन'' आरोपों से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री चुनाव घोषणा पत्र की तैयारियों के लिए लोगों की सलाह लेने के लिए ''भारत के मन की बात, मोदी के साथ'' कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस की और से लगातार जोर शोर से राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार का मसला उठाने से आसन्न आम चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन पर कोई असर होगा तो गोयल ने इसका उत्तर नहीं में दिया। गोयल ने कहा, ''हम लगभग पूरे देश में गए हैं और किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया है और न ही कोई इससे चिंतित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनका पूरा भरोसा है। भारत की जनता का नरेंद्र मोदी पर भरोसा है।'' उन्होंने कहा कि ''पूरी तरह आधारहीन'' आरोप लगाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इन आक्षेपों का कोई आधार नहीं है। इसलिए, मुझे नहीं लगता है कि यह चुनाव में कोई मुद्दा होगा।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी इस बात से खुश है कि राफेल कोई मुद्दा नहीं है, और ''विपक्ष इसी में व्यस्त है जबकि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान विकास पर है और वह लोगों तक पहुंच रही है।'' यह पूछे जाने पर कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ-साथ होंगे तो गोयल ने कहा कि इसकी संभावना नहीं है।

भारत बांग्लादेश के साथ साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है : सुषमा स्वराज

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत बांग्लादेश को अधिकतम संभव सहायता देने के लिए हमेशा तैयार है क्योंकि समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश भारत के राष्ट्रीय हित में है। शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश संयुक्त परामर्श समिति (जेसीसी) की पांचवीं बैठक स्वराज ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि दोनों पक्ष आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने समेत रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना जारी रखेंगे। स्वराज ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमिन के साथ जेसीसी बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। स्वराज ने कहा, ''मैं दोहराना चाहती हूं कि भारत प्रधानमंत्री शेख हसीना के विकास एजेंडा के पूर्ण समर्थन में खड़ा है।

पूर्व विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा बोले, राहुल गांधी की दखलंदाजी के कारण कांग्रेस से नाता तोड़ा

मैसूर, 10 फरवरी (ए)। कर्नाटक के पूर्व सीएम और मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री रहे एस एम कृष्णा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके कृष्णा ने कहा कि राहुल गांधी सरकार के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप करते थे। राहुल गांधी की दखलंदाजी के कारण उन्हें सरकार और कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। कर्नाटक के पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे और अपनी मर्जी से विधेयकों को महत्व देते थे। यूपीए 2 में विदेश मंत्री का पद संभालने वाले कृष्णा ने अपने पद छोड़ने का कारण भी राहुल गांधी को बताया। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकाल में विदेश मंत्रीके तौर पर मेरे विभाग में मनमोहन सिंह का दखल भी नहीं था। राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि 80 पार नेताओं को पद से छुट्टी करनी है और इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। यह किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं समझते थे। अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ विधेयकों को

महत्व देते थे और बाकी को लटका देते थे। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दखल से परेशान होकर उन्होंने विदेश मंत्री का पद छोड़ा था। 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के फैसले पर भी कृष्णा ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष की हस्तक्षेप करने की आदत ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, अपने पास काम करने का कोई और रास्ता नहीं देखकर मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी पर सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में भी दखल देने का आरोप कृष्णा ने लगाया। उन्होंने कहा, 10 साल पहले राहुल गांधी पार्टी में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं थे। पार्टी से जुड़े हर फैसले में वह हस्तक्षेप करते थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी राहुल गांधी के पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के लिए भेजे जाते थे, जबकि पीएम को इस विषय में जानकारी भी नहीं रहती थी। उन्हें हटाने का आदेश राहुल गांधी ने दिया क्योंकि वह 80 साल से अधिक उम्र के नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं देना चाहते थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कृष्णा सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति तभी होती है जब कोई निर्णायक नेतृत्व नहीं होता है। एस एम कृष्णा ने राहुल गांधी के हस्तक्षेप को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा, 2009 से 2014 तक मैं सरकार में था और सरकार के हर अच्छे-बुरे फैसले की जिम्मेदारी मुझ पर बनती है। कृष्णा ने यह भी आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री का सरकार, कैबिनेट और सहयोगी दलों पर कोई नियंत्रण नहीं था। सब कुछ पर कंट्रोल राहुल गांधी का था और वह ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि वह कोई अतिरिक्त संवैधानिक संस्था हों। विदेश मंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह भी कृष्णा ने राहुल गांधी को बताया। उन्होंने कहा कि बतौर विदेश मंत्री साढ़े तीन साल का उनका कार्यकाल बेहतरीन था। उन्हें हटाने का आदेश राहुल गांधी ने दिया क्योंकि वह 80 साल से अधिक उम्र के नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं देना चाहते थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कृष्णा सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो हैं।

अभिव्यक्ति की आजादी और दलित अधिकारों के मुखर वक्ता :आनंद तेलतुंबड़े

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। वह पेशे से भले ही मैनेजमेंट इंजीनियर हैं और फिलहाल गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके विचार और उनका लेखन उनके व्यक्तित्व का एक बहुत मुखर चेहरा दिखाता है, जिसमें व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने का माद्दा है और जो अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर दलित राजनीति तक तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। यह हैं जाने माने दलित शिक्षाविद् प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े। परिचय की बात करें तो आनंद तेलतुंबड़े एक स्तंभकार, शिक्षाविद् और मानव अधिकार कार्यकर्ता होने के साथ ही एक ऐसे लेखक हैं, जिनकी तमाम किताबों की जमकर आलोचना हुई। उन्होंने अपनी किताबों में आरक्षण और दलित राजनीति का एक विद्रूप चेहरा समाज के सामने लाने की कोशिश की है। उनकी अधिकतर किताबों का बहुत सी भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। समकालीन जन आंदोलनों पर बेखौफ कलम चलाने वाले आनंद सामयिक विषयों की लगभग सभी पत्रिकाओं आउटलुक इंडिया, तहलका, मेनस्ट्रीम, सेमीनार, फ्रंटियर और इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली में नियमित रूप से लिखते हैं। उनका नियमित स्तंभ 'मार्जिन स्पीक' अपने आप में व्यवस्था को आइना दिखाने का काम करता है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक छोटे से गांव राजुर में जन्मे आनंद ने गांव के ही एक स्कूल से सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की और उसके बाद वानी तालुका के सरकारी हाई स्कूल में दाखिला लिया। वहां से दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद आनंद ने इंटीट्यूट ऑफ साइंस से पी यूनिवर्सिटी और विश्वेसरैया रीजनल कालेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक उन्होंने विभिन्न कंपनियों में नौकरी की और फिर अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान में दाखिला लिया। उन्होंने साइबरनेटिक मॉडेलिंग में शोध किया, जिसके लिए उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय से पीएच डी की उपाधि प्रदान की गई। वह प्रोडक्शन रिसर्च, प्रोजेक्ट रिसर्च, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एरगोनोमिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और सायबरनेटिक्स जैसे गूढ़ विषयों पर दुनियाभर में अनतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहते हैं।

दिल्ली में हर साल औसतन 50 हजार गर्भपात प्रसव के दौरान मां की मौत का आंकड़ा भी बढ़ा

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले पांच साल के दौरान हर साल औसतन 50 हजार गर्भपात होने के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली दिल्ली में प्रसव के दौरान मां की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 2013-14 से 2017-18 के दौरान सरकारी और निजी स्वास्थ्य केन्द्रों पर 2,48,608 गर्भपात हुये। इनमें सरकारी केन्द्रों पर किये गये गर्भपात की संख्या 1,44,864 और निजी केन्द्रों का आंकड़ा इससे थोड़ा कम, 1,03,744 है। स्पष्ट है कि दिल्ली में हर साल औसतन 49,721 गर्भपात किये गये। सामाजिक कार्यकर्ता राजशंस बंसल के आरटीआई आवेदन पर दिल्ली सरकार के परिवार कल्याण निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, गर्भपात के दौरान पांच सालों में 42 महिलाओं की मौत भी हुयी। इनमें मौत के 40 मामले सरकारी केन्द्रों और दो मामले निजी केन्द्रों में दर्ज किये गये हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में इन पांच सालों में प्रसव के दौरान 2,305 महिलाओं की मौत हुयी। इनमें से 2,186 मौत सरकारी अस्पतालों में और सिर्फ 119 निजी अस्पतालों में हुयी। आंकड़ों के मुताबिक, प्रसव के दौरान मां की मौत का सिलसिला साल दर साल बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में यह संख्या 2013-14 में 389 से बढ़कर 2017-18 में 558 हो गयी है। जबकि निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान मां की मौत की संख्या 27 थी जो कि 2017-18 में 24 पर आ गयी है। दिल्ली में गर्भपात के मामले में मामूली राहत की बात यह रही कि बीते पांच सालों के दौरान चार साल तक गर्भपात में बढ़ोतरी के बाद पिछले साल गिरावट दर्ज हुयी है। आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 में कुल 49,355 गर्भपात हुये थे। इस संख्या में अगले तीन साल तक लगातार बढ़ोतरी होने के कारण 2016-17 में यह संख्या 55,554 हो गयी। अब 2017-18 में यह आंकड़ा 39,187 ही गया है। इन आंकड़ों के जिले वार विश्लेषण से पता चला है कि पांच सालों में पश्चिमी जिले में सर्वाधिक, 39,215 और उत्तर पूर्वी जिले में सबसे कम, 8294 गर्भपात हुये। दिल्ली के 11 जिलों में यह एकमात्र जिला है।

ईवीएम-वीवीपैट मशीन पर पार्टियों ने पांच महीनों में बदली मांग

नई दिल्ली, 10 फरवरी (ए)। करीब 21 राजनीतिक पार्टियों ने 1 फरवरी को चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन पार्टियों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव में ईवीएम मशीन से पड़ने वाले वोटों में से कम से कम 50 प्रतिशत का वीवीपैट मशीन (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) के जरिए मिलान होना ही चाहिए। गौर करने वाली बात है कि 5 महीने पहले इस बारे में इनकी राय अलग थी। पिछले साल 27 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की गई ऑल-पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने 30वें, एनसीपी ने 33वें, सीपीएम ने 10वें और आम आदमी पार्टी ने 20वें ईवीएम वोटों का मिलान वीवीपैट स्लिप से कराने का प्रस्ताव दिया था। वहीं बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस और नैशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बैलट पेपर सिस्टम को वापस लाने की बात भी कही थी।

विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की 27 अगस्त की मीटिंग से

संबंधित दस्तावेज टाइम्स ऑफ इंडिया को मिले हैं। इसके मुताबिक, डीएमके, जनता दल (सेक्युलर), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और टीडीपी ने पिछले हफ्ते एक साझा अर्जी में 50 प्रतिशत वोटों के ईवीएम-वीवीपैट मशीन से मिलान की मांग की है। इसके अलावा जिन जगहों पर जीत का अंतर 5 प्रतिशत से कम रहे, वहां 100 प्रतिशत ईवीएम वोटों का मिलान वीवीपैट मशीनों से होना चाहिए। इन पार्टियों ने सीधे तौर पर अब ईवीएम की खारिज नहीं किया है बल्कि पेपर ट्रेल काउंट के सिस्टम में सुधार का सुझाव दिया है। बता दें कि अभी एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम काउंट के लिए वीवीपैट स्लिप का मिलान होता है। करीब 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। 1 फरवरी को चुनाव आयोग से मुलाकात से पहले कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। 27 अगस्त को ईवीएम में गड़बड़ी और कथित तौर पर पार्टी विशेष को ही वोट पड़ने का हवाला देते हुए ईवीएम की विश्वसनीयता पर से जुड़े प्रश्न पूछे थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने सलाह दी थी कि पुराने और नए ईवीएम मॉडल को जनता के सामने लाना चाहिए और कम से कम 30 प्रतिशत वोटों का मिलान वीवीपैट से होना चाहिए। कांग्रेस ने यहां तक कहा था कि चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी को वापस पाने के लिए बैलट पेपर सिस्टम की जरूरत है।

तृणमूल ने जहां बैलट पेपर की वापसी की मांग की थी, वहीं बीएसपी चाहती थी कि चुनाव आयोग वीवीपैट स्लिप के आंकड़े को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। बीएसपी ने यह भी कहा था कि बेहतर होगा बैलट पेपर सिस्टम को ही वापस लाया जाए।

प्रिंस फिलिप ने सरेंडर किया ड्राइविंग लाइसेंस, पिछले महीने कर दिया था कार एक्सीडेंट

लंदन, 10 फरवरी (ए)। मझारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति 97 वर्षीय प्रिंस फिलीप ने गत माह में हुई कार दुर्घटना के बाद शनिवार को अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। बता दें कि प्रिंस फिलीप की कार दुर्घटना के बाद काफी विवाद हुआ था। मीडिया में बढ़ती उम्र में वाहन चलाने को लेकर गंभीर चर्चा छिड़ गई थी। बकिंघम पैलेस ने बताया कि प्रिंस फिलीप ने पिछले महीने हुए लैंड रोवर दुर्घटना के बाद स्वयं यह फैसला लिया।पैलेस की ओर से जारी बयान के अनुसार, गंभीरता से विचार करने के बाद स्वेच्छा से अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला लिया है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नोरफोक पुलिस इसकी पुष्टि करती है कि सैंड्रिघम दुर्घटना में शामिल लैंडरोवर के ड्राइवर ने स्वेच्छा से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। बता दें कि सैंड्रिघम रिसायत के नजदीक गत माह 17 जनवरी को एक कार से टक्कर के बाद प्रिंस की लैंड रोवर पलट गई थी। हालांकि, इस दौरान उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। दूसरी गाड़ी पर सवार दो महिलाएं और उसका ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। उस गाड़ी में एक बच्चा भी था। बताया जा रहा है कि सूर्य की तेज रोशनी में आंखें चौंधियाने से उनका संतुलन बिगड़ा जिस कारण यह हादसा हुआ। इसके बाद उस सड़क पर गाड़ी की गति सीमा भी कम कर दी गई है। ब्रिटेन में गाड़ी चलाने की उम्र की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, 70 साल का होने पर व्यक्ति का लाइसेंस रद हो जाता है। उसे नवीनीकृत नहीं कराने पर वह गाड़ी नहीं चला सकता।

सरकार व न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पर पाक पत्रकार गिरफ्तार

लाहौर, 10 फरवरी (ए)। न्यायपालिका, सरकारी संस्थानों और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ अपमानजनक और घृणित पोस्ट अपलोड करने पर शनिवार को एक पाकिस्तानी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। दीन न्यूज पर टॉक शो की एंकरिंग करने वाले रिजवान रजी को लाहौर स्थित घर से संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) ने गिरफ्तार किया। एफआइए ने कहा कि शुरुआती जांच में इस बात का पता चला है कि उसने अपने ट्विटर अकाउंट से यह अपमानजनक पोस्ट किए। जांच एजेंसी ने कहा कि रजी पहले जांच में शामिल हुए थे और अपने बयान में उन्होंने 2011 के बाद से ट्विटर अकाउंट से न्यायापालिका और अन्य विभागों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने की बात कबूल की थी। इसके लिए उन्होंने उस समय माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा करना जारी रखा।फ्रोरेंसिक डाटा से इस बात का पता चला है कि रजी ने ही न्यायापालिका, सरकारी संस्थानों और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ अपमानजनक और घृणित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड की हैं। रजी पर नए साइबर कानून पीपीईसीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी पर पत्रकार संगठनों के साथ-साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने निंदा की है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है।

इराक और फ्रांस ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

बगदाद, 10 फरवरी (ए)। इराक के प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल-माहदी ने बगदाद में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैरली से दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की। फ्लोरेंस शुक्रवार को इराक के दौरे पर पहुंची हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, माहदी के मीडिया कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि इराक के प्रधानमंत्री ने शनिवार को आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) से लड़ाई और आतंकि कप से विस्थापित लोगों की सहायता में फ्रांस की भूमिका की सराहना की। इस बीच, पैरली ने इराक में स्थिरता लाने और आईएस के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने पुनर्निर्माण प्रक्रिया और सेवाओं के विकास में इराक के साथ सहयोग जारी रखने के फ्रांस के नेताओं की इच्छा पर जोर दिया। पैरली शुक्रवार को एक औचक दौरे में इराक की राजधानी बगदाद पहुंची थीं। उन्होंने इराक के राष्ट्रपति बरहम सालिह से भी मुलाकात की और उनके साथ क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की।

जुलाई में अंतरिक्ष सैर पर निकलेंगे अरबपति रिचर्ड ब्रैन्सन

वॉशिंगटन,10 फरवरी (ए)। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैन्सन जल्द ही अपने वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। एयर एंड स्पेस म्यूजियम में वर्जिन गैलेक्टिक के सम्मान समारोह के दौरान ब्रैन्सन ने यह खुलासा किया है। बकौल ब्रैन्सन, मेरी इच्छा है कि चांद पर कदम रखने की 50वीं वर्षगांठ पर अगले चार-पांच माह के भीतर मैं अंतरिक्ष यात्रा पर जाऊं। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन दो ऐसी कंपनियां हैं जो यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि लोगों की यह यात्रा महज कुछ ही मिनट के लिए होगी। कंपनियां यात्रियों को सब-ऑर्बिटल उड़ानों पर भेजने की योजना बना रही हैं ताकि लोग अंतरिक्ष यात्रा का लुत्फ ले सकें। सबऑर्बिटल उड़ानों के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा का चक्कर नहीं लगाएंगे। माना जा रहा है कि यह मिशन वर्ष 2023 तक जापानी अरबपति को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने वाले स्पेसएक्स के मिशन से सस्ते होंगे। भारत अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर गगनयान परियोजना की घोषणा की थी। इसके मुताबिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन भेजेगा। इसमें वैज्ञानिक के साथ एक आम नागरिक को भी जाने का मौका दिया जाएगा। इसरो अध्यक्ष डॉ. के सिवन के अनुसार, हम चाहते हैं कि अंतरिक्ष में कोई महिला वैज्ञानिक जाए। यह हमारा लक्ष्य है। हम पुरुष और महिला, दोनों वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करेंगे। अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो चयन करेगा। सामान्य तौर पर कोई भी आम नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है।

वेनेजुएला की सेना ने मादुरो के प्रति वफादारी खत्म करने की घोषणा की

काराकास, 10 फरवरी (ए)। वेनेजुएला की सेना में डॉक्टर कर्नल रुबेन पाज जिमेनेज ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से अपनी वफादारी खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने विपक्ष के नेता जुआन गुएडो का समर्थन किया है। कर्नल ने शनिवार को जारी एक वीडियो में कहा, ''सशस्त्र बलों में हमारे में से 90 फीसदी लोग वास्तव में नाखुश हैं। हमें उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।'' उन्होंने अपने साथी सैनिकों से वेनेजुएला को मानवीय सहायता देने में मदद करने का अनुरोध किया।

अमेरिका से सहायता सामग्री लेकर आ रहा जहाज अभी सीमा पर कोलंबिया के कुकुटा में है। मादुरो ने जहाज को प्रवेश से रोकने का संकल्प जताया है। उन्होंने इसे अमेरिकी आक्रमण का अग्रदूत बताया। एक सप्ताह पहले ही वायु सेना जनरल फ्रांसिस्को यानेज ने भी मादुरो से अपनी वफादारी खत्म कर दी थी। वेनेजुएला में सत्ता में रहने के लिए सेना का समर्थन महत्वपूर्ण होता है।

2014 में सरकार बदलने के बाद से भारत-श्रीलंका संबंधों में गिरावट आई : राजपक्षे

बेंगलूरू, 10 फरवरी (ए)। श्रीलंका के विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को यहां कहा कि 2014 में नयी दिल्ली में नयी सरकार के गठन के बाद से भारत और उनके देश के द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी गिरावट आयी। हालांकि अब उनके नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन और भारत की सत्ताधारी पार्टी के बीच अच्छा समन्वय है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत-श्रीलंका संबंधों को लेकर अनुभव सिद्ध नियम यह होना चाहिए कि यदि एक निर्वतमान सरकार का उनके देश के साथ पर्याप्त कार्य संबंध है तो आने वाली सरकार को भी इसे उचित मान्यता देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में व्यवधान का खतरा पैदा हो जाता है। दोनों देशों के लिए ऐसे आसानी से टाले जा सकने वाले व्यवधानों के गंभीर परिणाम हुए हैं। यहां हिंदू के दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन, द हडल

के तीसरे संस्करण, में राजपक्षे ने कहा कि 2014 में द्विपक्षीय संबंधों में दूसरी बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। दुर्भाग्यवश, मेरी सरकार और निर्वतमान सरकार (यूपीए) के बीच मौजूद कामकाजी संबंध भारत में बनी नई सरकार (एनडीए) से नहीं रहे। राजपक्षे ने कहा कि 1980 और 2014 में जो गलतफहमियां थीं उन्हें आसानी से टाला जा सकता था। यह जरूरी है कि दोनों देश इन गलतफहमियों को पैदा होने से रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करें।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने संप्रभुता, गुटनिरपेक्षता, गैर-हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों का भी हमेशा सम्मान किया और उस पर खरे रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना ने पिछले साल अक्टूबर में विवादित तौर पर राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। इससे एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था जो करीब 50 दिन तक चला। बाद में श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के पद पर बहाल कर दिया था।